

न्यायालय उपजिला कलक्टर, अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:-सुरेश राव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-127/2023

जीसीएमएस नं. :-2023/371

1. कैलाश कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2. गजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
3. मन्जु कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
4. सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
5. सरोज कंवर पुत्री सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।

- प्रार्थीगण

बनाम्

1. राजेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी धमोरा तहसील व जिला झुंझुनू।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

-अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट

उपस्थित-

1. मनोहर लाल एडवोकेट प्रार्थीगण की ओर से
2. मूलाराम जागू एडवोकेट अप्रार्थी सं.-1 की ओर से

दिनांक :-13/03/26

- :: निर्णय :: -

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि 0वाके चक 35 ए पी डी तहसील अनूपगढ़ का खाता सं.-55/59 का पत्थर सं.-339/417 के किला नं.-11/2 से 25 की कल 5.755 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर सं.-339/421 मु.नं.-28 के किला नं.-1 ता 25 की कुल 6.315 हैक्टर कमाण्ड कुल 12.080 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं.-1 के नाम से संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जमाबन्दी की प्रति सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण यहां यह स्पष्ट करता है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण आपस में सगे भाई बहन हैं तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र में दर्ज अनुसार उक्त सयुक्त खाता की भूमि में अप्रार्थी सं.-1 के साथ बहिस्सा बराबर का हक अधिकार एवं अधिपत्य है जिसमें प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी सं.-1 का 1/3 हिस्सा है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.-1 उपरोक्तानुसार व सुविधानुसार अपने हिस्सा की भूमि पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त होकर उसका निरंतर उपयोग एवं उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी सं.-1 का 1/3 हिस्सा सयुक्त रूप से दर्ज है और अब पिछले कई समय हमारे बीच आपस में उक्त भूमि की काश्त, सिंचाई व उसका उपयोग, उपभोग करने में तथा अपने अपने हिस्सा अनुसार राजस्व कर व सिंचाई कर अदा करने में अक्सर विवाद होता रहता है। चूंकि उक्त विवादित भूमि मौका पर सयुक्त राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका अभी तक प्रार्थी एवं अप्रार्थी सं.-1 के मध्य खाता विभाजन नहीं हुआ है और ना ही अभी तक किसी हिस्सेदार के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट हुई है कि उक्त विवादित भूमि में किस हिस्सा पर व किस किला पर किस हिस्सेदार का कब्जा है। इसलिए प्रार्थीगण

82

सुरेश राव

उपजिला अधिकारी


अनूपगढ़



एवं अप्रार्थी सं.-1 के मध्य हर समय उक्त भूमि की काश्त सिंचाई आदि को लेकर व अपने अपने हिस्सा अनसार राजस्व कर एवं सिंचाई कर आदि को लेकर हर समय विवाद रहता है तथा जिस सम्बन्ध में प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.-1 से कई बार कहा कि अपने सभी जने सहमत होकर तहसील में चल कर अपने अपने हिस्सा अनुसार एवं भूमि की किस्म अनुसार भूमि का खाता विभाजन करवा लेवे ताकि प्रत्येक पक्ष अपने अपने हिस्से की भूमि को अच्छी तरह काश्त कर सके और उसका उपयोग उपभोग कर सके लेकिन अप्रार्थी सं.-1 हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता जिस पर बिलआखिरकार आज से अरसा पांच रोज पूर्व प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.-1 से अनुपगढ़ तहसील में चल कर भूमि की किस्म अनुसार अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी अनुसार राजस्व रिकार्ड में बटंवारा करवाने का कहा तो अप्रार्थी सं.-1 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गया तथा स्पष्ट कहा कि उसे बटंवारा की कोई जरूरत नहीं है प्रार्थीगण को जरूरत है तो वे करवा सकते हैं क्योंकि अप्रार्थी सं.-1 ज्यादा भूमि पर काश्त कर रहा है इसलिए वह किलेवाईज बटंवारा नहीं करना चाहता तथा अप्रार्थी सं.-1 ने प्रार्थीगण को कहा कि वह शिघ्र ही बिना खाता विभाजन करवाये विशिष्ट किलाजात की भूमि को अन्यत्र बैचान कर देगा व प्रार्थीगण के कब्जा में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को भी काश्त नही करने देगा जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं.-1 को समझाया मगर अप्रार्थी सं.-1 ने धमकी दी कि वह शिघ्र ही ऐसा करेगा आपने जो करना है कर लो। चूकि प्रार्थना पत्र में दर्ज कृषि भूमि प्रार्थीगण एव अप्रार्थी सं.-1 के नाम बहिस्सा बराबर सयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है लेकिन अप्रार्थी सं.-1 अपने हिस्सा से अधिक भूमि पर काश्त कर प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर कब्जा करना चाहता है और प्रार्थीगण की सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी कर रहा है इसलिए प्रार्थीगण कानूनी रूप से यह अधिकार है कि वे अपने हिस्सा की भूमि पर काबिज होकर काश्त करे व उसी अनुसार सिंचाई सुविधा प्राप्त कर पानी लगाने लेकिन अप्रार्थी सं.-1 प्रार्थीगण के कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में दखलन्दाजी कर रहा है और विवावित भूमि का बिना खाता विभाजन करवाये अपने हिस्से की भूमि को विशिष्ट किलाजात में अन्यत्र बैचान करने के प्रयासरत है जिस सम्बन्ध में अप्रार्थी सं.-1 ने यह स्पष्ट व एलानिया धमकी भी दी है प्रार्थीगण के कब्जा में दखलन्दाजी कर प्रार्थीगण को भी काश्त नही करने देगा जबकि अप्रार्थी सं.-1 को ऐसा करने का विधिक अधिकार नहीं है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि ताफैसला मूल वाद अप्रार्थीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि अप्रार्थी सं.-1 विवादित कृषि भूमि वाके चक 35 एपीडी तहसील अनुपगढ़ का खाता सं 55/59 का पत्थर सं.-339/417 के किला नं.-1/2 से 25 की कुल 5.755 हैक्टर कमाण्ड व पत्थर सं.-339/421 मु.नं.-28 के किला नं.-1 ता 25 की कुल 6.315 हैक्टर कमाण्ड कुल 12.080 हैक्टर कमाण्ड खातेदारी का बिना राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन करवाये उक्त कृषि भूमि के किसी विशिष्ट किलाजात का हस्तान्तरण रहन बैचान करने व रिकार्ड का किसी प्रकार से परिवर्तन करने व करवाने से तथा विवादित भूमि पर प्रार्थीगण के हिस्सा अनुसार उसके कब्जा काश्त व सिंचाई सुविधा में किसी प्रकार की वेजा मदाखलत करने व करवाने बाज वा ममनू रहे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं.-1 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं.-1 के पिता सुमेरसिंह को आवटित हुई थी। वादग्रस्त कृषि भूमि के अलावा सुमेरसिंह के नाम से


सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनुपगढ़

ग्राम धमोरा मे भी कृषि भूमि थी। वर्ष 1988 में सुमेरसिंह का देहांत होने के पश्चात प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 ने वादग्रस्त भूमि एवं ग्राम धमोरा की कृषि भूमि के संबंध मे हक त्याग कर दिया। जिस पर वादग्रस्त भूमि एवं ग्राम धमोरा की भूमि प्रार्थीगण सं.-2, 4 एंवम अप्रार्थी सं.-1 एवं हमारी माता गुलाब कंवर चारों को बहिस्सा बराबर प्राप्त हुई। हक त्याग के आधार पर गांव धमोरा की कृषि भूमि तो हम चारों के नाम से दर्ज हो गई परन्तु प्रार्थीगण ने बाद मे हक त्याग के दस्तावेज को छुपाते हए वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण एंवम अप्रार्थी सं.-1 के नाम से बहिस्सा बराबर दर्ज करवा ली जो कि झूठे एवं मिथ्या दस्तावेजो के आधार पर दर्ज की गई है। प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 का वादग्रस्त भूमि मे कोई हिस्सा नही है। अप्रार्थी सं.-1 वर्षों से वादग्रस्त भूमि में से 12-10 बीघा भूमि पर शांति पूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा था पिछले दो वर्षों से 16-1 बीघा पर काश्त करता आ रहा है। प्रार्थीगण ने जानबूझ कर बेईमानी पूर्वक आश्रय से प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 द्वारा किये गये हक त्याग के दस्तावेज को छुपा कर इंतकाल दर्ज करवा लिया। प्रार्थीगण सं 1, 3 वा 5 का वादग्रस्त भूमि पर कोई कब्जा नही है। इंतकाल की कार्यवाही के आधार पर कब्जा करने के आश्रय से प्रार्थीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुके हैं इस कारण उनके कोई हित प्रभावित नही हो रहे है व ना ही किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 ने अपने पिता सुमेरसिंह की मृत्यु के पश्चात विवादित कृषि भूमि धमोरा की भूमि के संबंध मे अपने अधिकारों का त्याग कर दिया था उसी आधार पर ग्राम धमोरा की कृषि भूमि प्रार्थीगण सं.-2, 4 एंवम अप्रार्थी सं.-1 व हमारी माता गुलाब कंवर के नाम से दर्ज हो गई थी। चूकि वादग्रस्त भूमि सुरेन्द्रसिंह ही ठेका/हिस्सा पर देकर जाता था उसने अप्रार्थी सं.-1 को बताया कि चक 35 एपीडी वाली भूमि का इंतकाल हम तीनों भाईयों व माता के नाम से दर्ज हो चुका है इसी कारण सुरेन्द्रसिंह मुझ अप्रार्थी सं.-1 को 12-10 बीघा का ठेका देता रहा। हमारी माता के देहांत के बाद मुझ अप्रार्थी ने सुरेन्द्रसिंह से तीसरे हिस्से यानि आधा बीघा का ठेका मांगा तो वह मुझ अप्रार्थी सं.-1 से झगडा करने लगा जिस पर मुझ अप्रार्थी सं.-1 ने पिछले अपनी 16-10 बीघा भूमि स्वयं काश्त करनी शुरू कर दी। जिस पर सुरेन्द्रसिंह ने अन्य प्रार्थीगण को अपने प्रभाव मे लेकर हक त्याग के दस्तावेजो को छुपाते हुऐ भूमि का बहिस्सा बराबर विरासतन इंतकाल दर्ज करवा कर झूठे वादग्रस्त तथ्यों के आधार पर यह वाद पत्र प्रस्तुत किया है चूकि प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुकी है इस कारण वे किसी प्रकार का वादग्रस्त भूमि मे हक प्राप्त करने एंवम बंटवारा करवाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र एव वकालतनामा मे सुरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर नही है इस कारण प्रार्थना पत्र काबिले निररती के है। प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में किये गए हक त्याग के दस्तावेज प्रार्थीगण के कब्जा मे है जिसे उन्होने छुपा कर यह वाद प्रस्तुत किया है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय दर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

न्यायालय द्वारा बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस के दौरान कथित अभिवचनों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजातों, अप्रार्थीया के जवाब एवं स्टेट जवाब का अवलोकन किया गया। धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिये हमारे समक्ष तीन बिन्दू है। जिन पर न्यायालय का विवेचन इस प्रकार से है:-

81

सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

प्रथम दृष्ट्या प्रकरण :- यह कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित किया है कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खाता की सम्पति है। जिसमें प्रार्थीगण का हित निहित है। प्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते हैं तथा अप्रार्थी को इस अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहते हैं कि वे अपनी भूमि विक्रय या हस्तान्तरित नहीं करे। विधि का यह सुरथापित सिद्धान्त है कि सह-खातेदार काश्तकार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता और ना ही सह-खातेदार काश्तकार को उसके हिस्से की भूमि का बेचान करने से निर्बन्धित किया जा सकता है। सह-खातेदार बिना विभाजन करवाये अपनी सम्पति को विक्रय करने अथवा काश्त करने के हकदार है। प्रार्थीगण सं.-1, 3 वा 5 अपने हिस्से का हक त्याग कर चुके हैं इस कारण वे किसी प्रकार का वादग्रस्त भूमि में हक प्राप्त करने एवं बंटवारा करवाने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थन पत्र एवं वकालतनामा में सुरेन्द्रसिंह के हस्ताक्षर कही नहीं हैं। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के हिस्से की भूमि पर अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने या अप्रार्थी को उनके हिस्से की भूमि विक्रय/हस्तान्तरित व काश्त करने से निर्बन्धित करवाने के अधिकारी नहीं हैं। तथा प्रार्थीगण अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत बहस के तथ्यों से भी उक्त तथ्य व विधिक सिद्धान्तों को बल मिलता है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

सुविधा का संतुलन:-जहाँ तक सुविधा का संतुलन का तथ्य है। प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नहीं होता है ऐसी स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो प्रार्थीगण के अपेक्षा अप्रार्थी को ज्यादा असुविधा होगी तथा अप्रार्थी अपनी जरूरतों से वंचित हो जायेंगे एवं अप्रार्थी कानून द्वारा प्रदत्त अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। इस प्रकार सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

अपूर्णय क्षति:-प्रथम दृष्ट्या प्रकरण एवं सुविधा का संतुलन अप्रार्थी के पक्ष में तय हो चुके हैं तथा प्रार्थीगण अपने पक्ष में दोनों बिन्दू साबित करने में असफल रहे हैं। अप्रार्थी जो कि सह-खातेदार काश्तकार है इस स्थिति में अगर अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी अपने कानूनी अधिकारों से वंचित हो जायेंगे। जिससे अप्रार्थीगण को अपूर्णय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में अपूर्णय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित/सिद्ध नहीं है।

--: आदेश :-

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के विरुद्ध तय किये गये हैं। प्रार्थीगण न्यायालय से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. के माध्यम से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 राज. काश्त. अधिनियम खारिज किया जाता है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 13/03/26 को सरे इजलास सुनाया गया।



सुरेश राव
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड न्यायाधीश
अनूपगढ़